मंत्री जी मुझे 'घर' वापस बुला लो

विभूति कुमार रस्तोगी, नई दिल्ली

• आइटीएस के अधिकारियों ने एमटीएनएल और बीएसएनएल से मांगी मुक्ति

'मंत्री जी मुझे 'घर' वापस बुला लो,' कुछ इसी मार्मिक अंदाज में भारतीय दूरसंचार सेवा (आइटीएस) के अधिकारियों ने खुद को दूरसंचार मंत्रालय में वापस बुलाने का अनुरोध किया है। आइटीएस अधिकारियों ने एमटीएनएल और बीएसएनएल से मुक्ति मांगते हुए दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वे डेढ़-दो दशक से एमटीएनएल और बीएसएनएल में प्रतिनियुक्ति पर हैं। यह प्रतिनियुक्ति नियम के खिलाफ है। नियम के अनुसार प्रतिनियुक्ति में केवल सात साल तक ही रहा जा सकता है।

इन अधिकारियों का एक दर्द यह भी है कि उन्हें जो भत्ता मिलता है वह मंत्रालय में काम करने वाले आइटीएस अधिकारियों से काफी कम होता है। क्योंकि एमटीएनएल और बीएसएनएल पब्लिक सेक्टर यूनिट (पीएसयू) हैं। इन दोनों जगहों पर डीजीएम, जीएम से लेकर ईडी और सीएमडी स्तर पर आइटीएस अधिकारी ही हैं। एमटीएनएल-बीएसएनएल में करीब 16 सौ आइटीएस अधिकारी काम कर रहे हैं। दरअसल मामला यह है कि पूरे देश में टेलीफोन की सेवा दूरसंचार विभाग (डीओटी) के जिम्मे थी। सबसे पहले सन् 1986 में सरकार ने दिल्ली व मुंबई में टेलीफोन सेवा के लिए महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड नाम से पीएसयू का गठन किया।

उस दौरान आइटीएस अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया। ठीक उसी प्रकार एक अक्टूबर 2000 में देश भर में टेलीफोन सेवा को बीएसएनएल बनाकर पीएसयू के हाथों में दे दिया गया। इस दौरान भी दर्जनों आइटीएस अधिकारी एरिया मैनेजर, डीजीएम, जीएम आदि बनाए गए। ये अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर आए थे। इंडियन टेलीकॉम सर्विस एसोसिएशन के अध्यक्ष एनके छोकर और महासचिव ए.एस मीणा ने दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब आइटीएस अधिकारी एमटीएनएल और बीएसएनएल में नहीं रहना चाहते हैं।

उन्होंने कहा कि पहले दूरसंचार विभाग में काम नहीं था तो ये अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए थे, लेकिन अब तो मोबाइल, बेसिक, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में काफी काम बढ़ गए हैं।